



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 10—जनवरी 16, 2004 (पौष 20, 1925)
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 10—JANUARY 16, 2004 (PAUSA 20, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

सं. एन-15/13/6/5/2003-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम, 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जनवरी 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

“जिला त्रिशूर के तल्ला पिल्ली तालुक में अलूर के अधीन आने वाले क्षेत्र”।

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

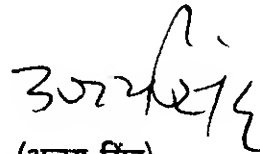
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मुख्यालय-भविष्य निधि भवन,
14, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066, दिनांक.30 दिसम्बर 2003

संख्या - सम्मेलन-5(1)/2002/आंध्र प्रदेश/18723

सं०..... कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (1) के अनुसरण में, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) एतद्वारा श्री के. भास्कर शर्मा, अध्यक्ष, बी.एम.एस.(आंध्र प्रदेश), टी.आर.टी.-141, स्ट्रीट नं० 9, जवाहर नगर, हैदराबाद-500020 को स्वर्गीय श्री आर.एल.एन.राजू, उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, आर.टी.सी. एक्स रोड, हैदराबाद के स्थान पर क्षेत्रीय समिति (कर्मचारी भविष्य निधि), आंध्र प्रदेश राज्य का सदस्य नियुक्त करते हैं तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या सम्मेलन-5(1)/ 2002/आंध्र प्रदेश/14428 दिनांक 6.11.2003 में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं।

उक्त अधिसूचना में कर्मचारी के प्रतिनिधि पक्ष के अंतर्गत योजना के पैरा 4(1)(घ) में सदस्य के रूप में क्रम संख्या 6 पर की गयी प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :-

श्री के. भास्करा शर्मा,
अध्यक्ष, बी.एम.एस.(आंध्र प्रदेश),
टी.आर.टी.-141, स्ट्रीट नं० 9, जवाहर नगर,
हैदराबाद-500020


(अजय सिंह)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली. दिनांक 26 दिसम्बर 2003

यूजीसी (विनिर्दिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश) अन्तरिम विनियम 2003

सर्वोच्च न्यायालय की 11 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 को टी.एम.ए. पर्ई फाउंडेशन तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य तथा अन्य के मामले में दिए गए निर्णय के साथ पठनीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 14 अगस्त 2003 को इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य तथा अन्य के मामले में दिये गये निर्णय के पालन हेतु, तथा प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों पर पड़ने वाले मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक बोझ का परिहार करने के लिये, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 की सं.3) की धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (जी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अन्तरिम नीति विनियम सं.एफ.1-6/2003(सीपीपी-2) दिनांक 10 जून, 2003 का आंशिक अधिक्रमण करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देशभर में विनिर्दिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वर्ष 2004-2005 के दौरान प्रवेश हेतु निम्नलिखित अन्तरिम विनियम बनाता है।

1. लघु शीर्षक, लागू होना पत्र एवं प्रारम्भ :

- (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विनिर्दिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश) अन्तरिम विनियम 2003 कहा जाये।
- (2) ये केंद्रीय, प्रान्तीय अथवा राज्य अधिनियमों के द्वारा स्थापित अथवा समाविष्ट सभी विश्वविद्यालयों सहित इन से सम्बद्ध अथवा मान्य समस्त संस्थानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत आने वाले सभी मानित विश्वविद्यालयों, जो विनिर्दिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाते हैं, पर लागू होंगे।
- (3) ये विनियम वर्ष 2004-2005 के दौरान विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के प्रवेश पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

जब तक प्रसंगत: अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में :-

2.1 'संस्थान' से अभिप्राय है वे सभी विश्वविद्यालय जो केंद्र, प्रान्त अथवा राज्य अधिनियमों के द्वारा स्थापित अथवा समाविष्ट हों तथा इनमें से किसी से भी सम्बद्ध अथवा मान्य संस्थान हों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 3 के अन्तर्गत आने वाले सभी मानित विश्वविद्यालय ।

2.2 "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्राय है :

- (i) आयोग या आयोग द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में नामोद्दिष्ट कोई एजेंसी : केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, किसी निजी ट्रस्ट अथवा सोसाइटी द्वारा स्वयं अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 25 अथवा केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत गठित विश्वविद्यालय अथवा केन्द्रीय सरकार तथा किसी निजी ट्रस्ट अथवा सोसायटी अथवा कंपनी के संयुक्त उद्यम के रूप में गठित विश्वविद्यालय तथा इन अथवा अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध अथवा मान्य निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्थान हैं ।
- (ii) राज्य/केन्द्र शासित सरकार अथवा इस परिप्रेक्ष्य में नामोद्दिष्ट एजेंसी : राज्य विश्वविद्यालयों किसी निजी ट्रस्ट अथवा सोसायटी के द्वारा स्वयं अथवा कंपनी ऐक्ट की धारा 25 के अंतर्गत अथवा राज्य/संघ शासित क्षेत्र के विधान के द्वारा स्थापित अथवा राज्य/संघ शासित सरकार तथा निजी ट्रस्ट या सोसायटी या कंपनी के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित विश्वविद्यालय तथा इन एवं अन्य राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध या मान्य राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर कार्यरत व्यावसायिक शैक्षिक संस्थान ।

3. सामूहिक प्रवेश परीक्षाएँ :

वर्ष 2004-2005 के दौरान देशभर में विनिर्दिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्धारित योग्यता के आधार पर सामूहिक प्रवेश परीक्षाओं के द्वारा किया जाएगा जो निम्नवत् है ।

3.1. अखिल भारतीय सामूहिक प्रवेश परीक्षाएँ :

ये परीक्षाएँ उन सभी संस्थानों के लिये हैं जो इस समय सभी छात्रों का अथवा उनके कुछ प्रतिशत का प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर करते हैं।

3.1.1. स्नातक स्तर पर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एण्ड प्लानिंग तथा फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा

देशभर के संस्थानों में स्नातक स्तर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एण्ड प्लानिंग तथा फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश **अखिल भारतीय इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एण्ड प्लानिंग तथा फार्मेसी प्रवेश परीक्षा** (ए.आई.ई.ई.ई.) द्वारा किया जाएगा जिसका आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) करेगा। तथापि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस (धनबाद), तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) के प्रवेशों पर, जो छात्रों का प्रवेश अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर करते हैं, पर ए.आई.ई.ई.ई. लागू नहीं होगा।

3.1.2. मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन/प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (अथवा समकक्ष) हेतु प्रवेश परीक्षा

एम.बी.ए./पी.जी.डी.बी.एम. अथवा समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाँच 5 राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में से किसी एक के माध्यम से होगा - सी.ए.टी. (आई.आई.एम. संस्थानों द्वारा संचालित), जे.एम.ई.टी. (आई.आई.टी. संस्थानों द्वारा संचालित), एम.ए.टी. (ए.आई.एम.ए. द्वारा संचालित), ए.टी.एम.ए. (ए.आई.एम.एस. द्वारा संचालित) तथा एक्स.ए.टी. (एक्स.एल.आर.आई. द्वारा संचालित)। वे सभी संस्थान जो अखिल भारतीय स्तर पर छात्रों को प्रवेश देते हैं, इनमें से किसी एक परीक्षा को चुनेंगे तथा अपनी प्रवेश विवरणिका में इसकी घोषणा करेंगे।

3.1.3 मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षा

देशभर के सभी संस्थानों में एम.सी.ए. अथवा इसके समकक्ष किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की द्वारा संचालित **अखिल भारतीय एम.सी.ए. सामूहिक प्रवेश परीक्षा** (ए.आई.एम.सी.ए.ई.टी) के द्वारा होगा।

3.2. राज्य स्तरीय सामूहिक प्रवेश परीक्षाएँ

सभी राज्य राज्य कोटा के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में स्थित संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिये स्वयं अपनी सामूहिक प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित करेंगे। ये परीक्षाएँ केवल उसी राज्य के छात्रों के प्रवेश हेतु ही सीमित होंगी। तथापि जो राज्य अपनी सामान्य प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित नहीं करते, वे छात्रों का प्रवेश संबंधित अखिल भारतीय सामूहिक प्रवेश परीक्षा के योग्यता मानकों के आधार पर करेंगे।

4. विद्यमान अनुमोदित 'कोटा' के अंतर्गत प्रवेश, अपवाद रहित रूप से, संबंधित सामूहिक प्रवेश परीक्षा एवं तदुपरांत निर्धारित काउंसिलिंग में इंटर-से मेरिट के आधार पर होगा।

5. मैनेजमेंट कोटा

प्राइवेट गैर-सहायता स्ववित्तपोषित संस्थानों के मैनेजमेंट कोटा/सीटों को उपरिलिखित रीति से संचालित सामूहिक प्रवेश परीक्षा अथवा किसी अनुमोदित एजेंसी (राज्य में स्थित किसी विशेष कोटा के कालेजों के संघ इनमें शामिल हैं) द्वारा संचालित सामूहिक प्रवेश परीक्षा द्वारा भरा जाएगा। प्रबन्धन कोटा/स्थान भरने के इस विकल्प को संस्थानों द्वारा अपने प्रवेश विवरणिका निर्गत करने से पूर्व अपनाना होगा तथा सक्षम प्राधिकार को सूचित करना होगा।

6. प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सभी संस्थान सक्षम प्राधिकार को प्रविष्ट छात्रों की सूची देंगे जिसमें उस छात्र द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा में प्राप्त स्थान, उससे प्राप्त किया गया शुल्क तथा वे सभी सूचनाएँ तथा विवरण होंगे, जो सक्षम प्राधिकार द्वारा अपेक्षित है।

7. दंड

यदि किसी भी छात्र का प्रवेश बिना योग्यता के किया गया तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उस संस्थान पर जुर्माना किया जाएगा तथा मामले की गंभीरता के अनुसार उसकी मान्यता/सम्बद्धता भी वापिस ली जा सकती है।

अनुमति 26/12/03
(प्रो. वेद प्रकाश)
सचिव


होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली

प्रत्येक

साधारण सूचना

होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन रहे गए होमियोपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर के भाग 2 में अंतर्निहित सभी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों को इसके द्वारा यह साधारण सूचना दी जाती है कि उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् रजिस्ट्रीकरण विनियम, 1982 के विनियम 9 §1§ में यथा उपबन्धित उक्त रजिस्टर में अपने नाम बनाए रखने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन करना होगा।

आवेदन के विहित प्रत्येक सहित साधारण सूचनाएं प्रत्येक ऐसे व्यवसायी को, उक्त रजिस्टर में दर्ज उसके पते पर डाक-प्रमाणपत्र के अधीन भेजी जा रही हैं। रजिस्टर में नाम बनाए रखने के प्रत्येक में आवेदन इस सूचना के जारी किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर सम्यक रूप से भर कर मुझे लौटा दिया जाना चाहिए। कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी जिसे डाक द्वारा प्रत्येक प्राप्त नहीं हुआ है रजिस्ट्रार के कार्यालय से उसे प्राप्त कर सकता है।


रजिस्ट्रार
होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद्

तारीख


स्थान : नई दिल्ली.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 19th December 2003

No. N-15/13/6/5/2003-P&D: In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st Jan. 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely

"Aloor in Thalappilly Taluk in Trichur District."


(R.C. SHARMA)
JOINT DIRECTOR (P&D)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
HEAD OFFICE -

NEW DELHI - 1100 66, the 30th December 2003

No. Conf. 5 (1) 2002/Andra Pradesh/18723

No. _____ In pursuance of Sub-Paragraph (1) of paragraph 4 read with Paragraph 5 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952, the Chairman, Central Board of Trustees (EPF) hereby appoints Shri K. Bhaskara Sharma, President, BMS(Andhra Pradesh), TRT-141, Street No.9, Jawahar Nagar, Hyderabad-500 020 in place of Late Shri R.L.N. Raju, Vice President, Bharatiya Mazdoor Sangh R.T.C. X Roads, Hyderabad, as a member in the Regional Committee (EPF) for the state of Andhra Pradesh, and makes the following amendments in the Notification of the E.P.F. Organisation, Head Office, New Delhi vide No. Conf. 5(1)2002/Andra Pradesh /14428 Dated 06.11.2003.

In the said Notification under the category of Employees' Representative vide para 4(1)(d) of the Scheme, for the entries against serial No.6, the following shall be substituted, namely:-

Shri K. Bhaskara Sharma,
President, BMS(Andhra Pradesh),
TRT-141, Street No.9, Jawaharnagar,
Hyderabad - 500 020.


(AJAI SINGH)
Central Provident Fund Commissioner

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION**NEW DELHI, 26th December, 2003****UGC (ADMISSION TO SPECIFIED PROFESSIONAL PROGRAMMES)
INTERIM REGULATIONS, 2003**

In pursuance of the Judgment on August 14, 2003 of the 5 Judge Bench of the Supreme Court in the case of Islamic Academy of Education and Ors. V. State of Karnataka and Ors. read with Majority Judgment on October 31, 2002 of 11 Judge Constitution Bench of the Supreme Court in the case of TMA Pai Foundation and Ors. V. State of Karnataka and Ors. and with a view to avoiding mental, physical and financial burden on students due to multiplicity of entrance examination(s), and in exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (No.3 of 1956), and in partial supersession of Interim Policy Regulations No.F.1-6/2003 (CPP-II) dated 10th June, 2003, the University Grants Commission (UGC) makes the following Interim Regulations for admission to specified professional programmes in the country during the year 2004-2005

1. Short title, application and commencement:

- (1) These Regulations may be called the University Grants Commission (Admission to specified professional programmes) Interim Regulations, 2003.
- (2) They shall apply to every university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, including all institutions recognized by/ or affiliated to them and every Institution deemed to be University under Section 3 of the UGC Act, 1956 conducting specified professional programmes.
- (3) They shall come into force for all admissions to the specified programmes during the year 2004-2005.

2. Definitions

In these Regulations unless the context otherwise requires:-

- 2.1. **"Institution"** means every university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, including all institutions recognized by or affiliated to them and every Institution deemed to be University under Section 3 of the UGC Act, 1956.
- 2.2. **"Competent Authority"** means:
 - (i) The Commission or its designated agency in relation to the Central Universities, deemed universities, universities set up by a private trust or a society on its own or under Section 25 of the Companies Act or under a Central legislation, or universities set up as a joint venture between the Central Government and a private trust or society or company, and private professional

educational institutions affiliated to or recognized by such or other Central universities;

- (ii) The State / Union Territory Government or its designated agency in relation to State Universities, universities set up by a private trust or a society on its own or under Section 25 of the Companies Act or under a State / Union Territory legislation, or universities set up as a joint venture between the State / Union Territory Government and a private trust or society or company, and professional educational institutions within the State affiliated to or recognized by such or other State universities.

3. Common Entrance Examination(s)

The admissions to specified professional programmes in the country for the year 2004-2005 shall be made on the basis of merit determined through common entrance examination(s) as enumerated below:-

3.1. All India Common Entrance Examination(s)

These examinations shall be for all the Institutions that are presently admitting all their students or certain percentage of them on an All India basis.

3.1.1. Entrance Examination for admissions to undergraduate programmes in Engineering, Architecture & Planning and Pharmacy

Admissions on All India basis to the undergraduate programmes in Engineering, Architecture & Planning and Pharmacy in all Institutions in the country shall be made through an All India Engineering, Architecture & Planning and Pharmacy Entrance Examination (AIEEE) conducted by the Central Board of Secondary Education (CBSE). The AIEEE shall, however, not be applicable for admissions to Indian Institute of Technologies, Indian School of Mines (Dhanbad) and Institute of Technology (Banaras Hindu University) that are admitting students on the basis of Joint Entrance Examination conducted by the Indian Institute of Technologies.

3.1.2. Entrance Examination for admissions to Master in Business Administration /Postgraduate Diploma in Management (or equivalent) programmes

Admissions to MBA/PGDM or equivalent programmes shall be through one of the five (5) national entrance examination(s), namely – CAT (conducted by IIMs), JMET (conducted by IITs), MAT (conducted by AIMA), ATMA (conducted by AIMS) and XAT (conducted by XLRI). All institutions admitting students on All India basis will have to opt for one of these exams and announce it in their prospectus.

3.1.3. Entrance Examination for admissions to Master of Computer Application programmes

Admissions to the MCA or equivalent programmes in all institutions in the country on an All India basis shall be made through an All India MCA Common Entrance Test (AIMCAET) conducted by IIT, Roorkee.

3.2. State Level Common Entrance Examination(s)

All States shall hold their own common entrance examinations for admissions to Institutions within their States for students to be admitted against the State quota. These examinations shall be restricted to admission of students from within the State only. However, admission of all students by those States which do not conduct their own entrance examination shall be made using the merit determined by the relevant All India Common Entrance Examination.

4. Admissions under the existing approved quotas shall be made strictly on the basis of inter-se merit in the relevant common entrance examination followed by counseling as prescribed.


5. Management Quota

Management quota / seats in private unaided self-financing institutions shall be filled either by the Common Entrance Examination as above or through a Common Entrance Examination conducted by an approved agency (including an Association of all colleges of a particular type in the State). This option for filling up management quota / seats shall be exercised by the institutions before issue of prospectus and intimated to the Competent Authority.

6. After the admission process is over, all Institutions shall submit to the Competent Authority the list of students admitted, along with their ranks obtained in the Common Entrance Examination by the students, the fees collected and all such particulars and details as may be required by the Competent Authority.

7. Penalty

If it is found that any student has been admitted de hors merit, penalty shall be imposed on that Institution as per the provisions contained in the UGC Act and in appropriate cases recognition / affiliation may also be withdrawn.


(Prof. Ved Prakash)
Secretary

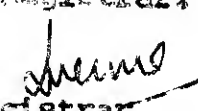
CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY,
NEW DELHI

FORM D

GENERAL NOTICE

General Notice is hereby given to all the Registered Practitioners included in Part-II of the Central Register of Homoeopathy maintained under the Homoeopathy Central Council Act, 1973 that they have to make an application to the Registrar for continuance of their names on the said Register as provided in regulation 9(1) of the Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1982, framed under the said Act.

Individual notices alongwith the prescribed form of application are being sent under certificate of posting to every such Registered Practitioner to the address entered in the said Register. An application in Form D for continuation of the name in the Register should be returned to the undersigned duly completed within 30 days of the issue of this notice. Any Registered Practitioner not receiving the Form by post may obtain it from the office of the Registrar.


Registrar
Central Council of Homoeopathy

Dated:

Place: New Delhi.

"DB"